Publication	The Indian Express	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	13/04/2023	Page no	6
CCM	17.52		

Govt allows PACS to convert wholesale consumer pumps into retail outlets

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 12

THE MINISTRY of Petroleum and Natural Gas agreed to convert existing Wholesale Consumer Licensed Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into retail outlets, the Cooperation Ministry said on Wednesday.

In a statement, the ministry said, "The existing PACS will be given a one-time option to convert their wholesale consumer pumps into retail outlets, provided they fulfil all the requirements for setting up retail outlets in rural areas, including statutory approvals and other permissions."

The statement came after Cooperation Minister Amit Shah held a meeting with Petroleum Minister Hardeep Puri on Wednesday. "On the initiative of the Ministry of Cooperation, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has taken several steps to strengthen PACS and cooperative sugar mills, such as PACS will be given priority in allotment of new petrol/diesel dealerships – this will strengthen cooperative movement," the statement said.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	The Economic Times	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	13/04/2023	Page no	9
CCM	8.15		

Agri Bodies can Convert Wholesale Petrol Pumps into Retail Outlets

New Delhi: In a major step to strengthen cooperatives, the government on Wednesday said existing Primary Agricultural Credit Societies (PACS) having wholesale petrol and diesel dealership licence will be given a one-time option to covert their bulk consumer pumps into retail outlets. The cooperation ministry, in a statement, said PACS will also be given priority in allotment of new petrol/diesel dealerships to strengthen the cooperative movement. – PTI

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	The Economic Times	Language	English
Edition	Mumbai	Journalist	PTI
Date	13/04/2023	Page no	11
CCM	14.76		

Agri Bodies can Convert Wholesale Petrol Pumps into Retail Outlets

New Delhi: In a major step to strengthen cooperatives, the government on Wednesday said existing Primary Agricultural Credit Societies (PACS) having wholesale petrol and diesel dealership licence will be given a one-time option to covert their bulk consumer pumps into retail outlets. The cooperation ministry, in a statement, said PACS will also be given priority in allotment of new petrol/diesel dealerships to strengthen the cooperative movement in the country. PACS will also be able to get LPG distributorship and their eligibility has been approved.

These decision were taken in a meeting held by Cooperation Minister Amit Shah with Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri here.

"In order to strengthen the PACS, the Ministry of Petroleum & Natural Gas has given its consent for conversion of existing wholesale petrol/diesel dealership licensed PACS (PACS) into retail outlets," the cooperation ministry said. Under this, existing PACS will be given a one-time option to convert their bulk consumer pumps into retail outlets, it said. —**PTI**

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Amar Ujala	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	13/04/2023	Page no	13
CCM	45.32		

सुविधा

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में किया निर्णय

पैक्स को मिलेंगे पेट्रोल पंप व एलपीजी डीलरशिप लाइसेंस

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) भी अब पेट्रोल-डीजल पंप चला सकेंगी और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगी। केंद्र सरकार ने सहकारिता समितियों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, थोक पेट्रोल एवं डीजल डीलरशिप लाइसेंसधारी मौजूदा पैक्स को उनके अधिक उपभोक्ता वाले पंपों को खुदरा दुकानों में शामिल करने का एकमुश्त विकल्प दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत पेट्रोल और डीजल की नई डीलरशिप के आवंटन में भी पैक्स को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके अलावा पीएसीएस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले सकेंगे। इसके लिए उनकी पात्रता को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

1,00,000

पीएसीएस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगी

नियमों में भी किया जाएगा बदलाव

सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के नियमों में भी बदलाव करेगा। इसके तहत एक मॉडल बायलॉज तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से देश भर में लगभग 1 लाख पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगी। इससे 13 करोड़ से अधिक किसानों को 25 से अधिक गतिविधियों के जरिये आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएसीएस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है। इसके तहत पीएसीएस एक समान राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के जरिये नबार्ड से जुड़ेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगी 300 से अधिक ई सेवाएं : सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इसके तहत पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक ई-सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सहकारी समितियों की स्थापना का भी लक्ष्य है।

चीनी सहकारिता मिलों को प्राथमिकता

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत इथेनॉल बेचने में चीनी सहकारी मिलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। पैक्स को अपने दम पर खुदरा दुकानों को संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल खरीद के लिए अन्य निजी कंपनियों के साथ गठजोड़ करें।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Amar Ujala	Language	Hindi
Edition	Dehradun	Journalist	
Date	13/04/2023	Page no	13
CCM	N/A		

सुविधा | केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में किया निर्णय

पैक्स को मिलेंगे पेट्रोल पंप व एलपीजी डीलरशिप लाइसेंस

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) भी अब पेट्रोल-डीजल पंप चला सकेंगी और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगी। केंद्र सरकार ने सहकारिता समितियों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, थोक पेट्रोल एवं डीजल डीलरशिप लाइसेंसधारी मौजूदा पैक्स को उनके अधिक उपभोक्ता वाले पंपों को खुदरा दुकानों में शामिल करने का एकमुश्त विकल्प दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत पेट्रोल और डीजल की नई डीलरशिप के आवंटन में भी पैक्स को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके अलावा पीएसीएस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले सकेंगे। इसके लिए उनकी पात्रता को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

1,00,000
पीएसीएस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगी

नियमों में भी किया जाएगा बदलाव

सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के नियमों में भी बदलाव करेगा। इसके तहत एक मॉडल बायलॉज तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से देश भर में लगभग 1 लाख पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगी। इससे 13 करोड़ से अधिक किसानों को 25 से अधिक गतिविधियों के जरिये आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएसीएस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है। इसके तहत पीएसीएस एक समान राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के जरिये नबार्ड से जुड़ेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगी 300 से अधिक ई सेवाएं : सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इसके तहत पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक ई-सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सहकारी समितियों की स्थापना का भी लक्ष्य है।

चीनी सहकारिता मिलों को प्राथमिकता

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत इथेनॉल बेचने में चीनी सहकारी मिलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। पैक्स को अपने दम पर खुदरा दुकानों को संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल खरीद के लिए अन्य निजी कंपनियों के साथ गठजोड़ करें।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from
SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	13/04/2023	Page no	8
CCM	25.54		

पैक्स को थोक पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की मिलेगी मंजूरी

सहकारिता मंत्री अमित शाह व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की मौजदूगी में हुई बैठक में लिया गया फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली (पैक्स) को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। सरकार ने आगे कहा कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई एक बैठक में लिया गया। इसके अलावा बैठक में फैसला किया गया कि चीनी सहकारी मिलों को एथनाल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथनाल बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया, पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी वितरण के लिए पैक्स को योग्य बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करेगा। पैक्स को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी 2) के तहत रखा जाएगा। इसके अलावा पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है। इसके तहत पैक्स एक काम नेशनल साफ्टवेयर के जरिये नाबार्ड से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	Dehradun	Journalist	
Date	13/04/2023	Page no	14
CCM	N/A		

पैक्स को थोक पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की मिलेगी मंजूरी

सहकारिता मंत्री अमित शाह व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली (पैक्स) को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। सरकार ने आगे कहा कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई एक बैठक में लिया गया। इसके अलावा बैठक में फैसला किया गया कि चीनी सहकारी मिलों को एथनाल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथनाल बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया, पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी वितरण के लिए पैक्स को योग्य बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करेगा। पैक्स को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी 2) के तहत रखा जाएगा। इसके अलावा पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है। इसके तहत पैक्स एक काम नेशनल साफ्टवेयर के जरिये नाबार्ड से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from SAMVAD

Publication	Hindustan	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	13/04/2023	Page no	12
CCM	24.83		

थोक पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदल सकेंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यह फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में लिया गया।

सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली पीएसीएस को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि चीनी सहकारी मिलों को एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथनॉल बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया कि पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी वितरण के लिए पीएसीएस को योग्य बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करेगा। पीएसीएस को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी 2) के तहत रखा जाएगा।

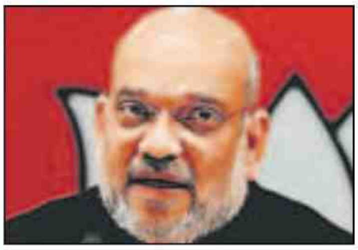

सहकारिता को मजबूत करने के लिए सरकार ने इजाजत दी

क्या हैं थोक पेट्रोल पंप : थोक पेट्रोल पंप पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन खरीदते हैं। इनसे बड़े बस-ट्रक ऑपरेटर और राज्य परिवहन आदि को ईंधन बेचा जाता है। यहां ईंधन के दाम आम पेट्रोल पंप से भिन्न होते हैं।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Hindustan	Language	Hindi
Edition	Dehradun	Journalist	
Date	13/04/2023	Page no	15
CCM	N/A		

थोक पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदल सकेंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यह फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में लिया गया।

सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली पीएसीएस को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि चीनी सहकारी मिलों को एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथनॉल बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया कि पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी वितरण के लिए पीएसीएस को योग्य बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करेगा। पीएसीएस को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी 2) के तहत रखा जाएगा।

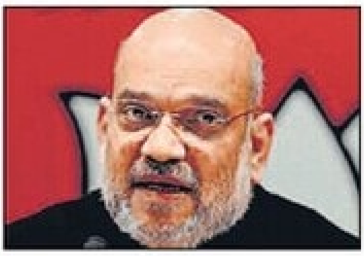

■ सहकारिता को मजबूत करने के लिए सरकार ने इजाजत दी

क्या हैं थोक पेट्रोल पंप : थोक पेट्रोल पंप पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन खरीदते हैं। इनसे बड़े बस-ट्रक ऑपरेटर और राज्य परिवहन आदि को ईंधन बेचा जाता है। यहां ईंधन के दाम आम पेट्रोल पंप से भिन्न होते हैं।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD